भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *261
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को डिजिटल सुविधाएं नहीं मिल पाना

***261. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :**

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, जहां डिजिटल अवसंरचना संबंधी केंद्रीय धनराशि के आवंटन में कथित विलंब हुआ है, में ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को डिजिटल सुविधाएं न मिल पाने की समस्या को किस प्रकार दूर कर रही है;

(ख) सरकार नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी कृत्यों संबंधी समस्या का किस प्रकार समाधान कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि बार-बार इंटरनेट बंद होने की समस्या के कारण देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को कितना आर्थिक और प्रतिष्ठात्मक नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ग)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को डिजिटल सुविधाएं नहीं मिल पाना के संबंध में दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *261 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

*****

(क) से **(ग) :** प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, भारत ने तीन-आयामी रणनीति: इंटरनेट तक पहुंच का विस्तार, इंटरनेट को किफायती बनाना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना का उपयोग करके डिजिटल अंतर को ख़त्म कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप समावेशी डिजिटल विकास हुआ है।

आज, भारत उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है, जिन्होंने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। दरअसल, हाल ही में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा था कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जिसे दुनिया के किसी अन्य देश ने नहीं बनाया है।

इस दिशा में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाना:

पिछले एक दशक में इंटरनेट का उपयोग कई गुना बढ़ गया है।

वर्ष	**2014**	**2025**
इंटरनेट कनेक्टिविटी	25 करोड़	103 करोड़

(स्रोत: टीआरएआई)

4जी और 5जी नेटवर्क का तेजी से विस्तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल का विशाल नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप इंटरनेट तक पहुंच में भारी वृद्धि हुई है।

ख. इंटरनेट को किफायती बनाना:

भारत दुनिया में सबसे कम डेटा टैरिफ वाले देशों में से एक है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों पर उपलब्ध टैरिफ की तुलनात्मक जानकारी दी गई है:

देश	**अनुमानित लागत प्रति 1 जीबी (यूएसडी में)**
भारत	**~ 0.08 - 0.10 (सबसे कम)**
बांग्लादेश	~ 0.23-0.34
नेपाल	~ 0.27-0.43
श्रीलंका	~ 0.25-0.35
पाकिस्तान	~ 0.12-0.18
फ़्रांस	~ 0.16-0.20
जर्मनी	~ 2.14
वैश्विक औसत	**~ 2.59**

जैसा कि ऊपर तालिका से स्पष्ट है, भारत का दूरसंचार टैरिफ वैश्विक औसत से 25 गुना कम है। यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में लाई गई पारदर्शिता के कारण संभव हुआ है।

ग. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना:

भारत ने एक विशिष्ट डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है जिसने हमारे लोगों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों को सक्षम बनाया है।

आधार: 1.43+ बिलियन से अधिक आधार नंबर जनित किए गए हैं, जो एक सार्वभौमिक डिजिटल पहचान प्रदान करते हैं। इसने कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है।

आधार-लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (56 मंत्रालयों की 328 योजनाओं) से नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसने एक साथ कई दस्तावेजों की आवश्यकता को कम किया है और डुप्लिकेट या नकली लाभार्थियों की समस्या को समाप्त कर दिया है।

विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा 16,600 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण किए गए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में 10.67+ करोड़ आधार आईडी बनाई गई हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई): यूपीआई ने 460 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं और मासिक रूप से अरबों लेनदेन के साथ बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान को अपनाने में सक्षम बनाया है। यह प्लेटफॉर्म 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 685 बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।

यूपीआई भारत के 81% डिजिटल भुगतान और वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय आधार पर डिजिटल भुगतान के लगभग 49% को सशक्त बनाता है।इसलिए, इस त्रि-आयामी रणनीति के परिणामस्वरूप हमारे देश में पिछले दशक में समावेशी डिजिटल विकास हुआ है।

सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सुरक्षोपाय

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सार्वजनिक आपातकाल और जन सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए इंटरनेट को अस्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियमावली, 2024 और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

******